भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2720**
11.12.2024 को उत्तर देने के लिए

सरकारी आंकड़ों की सटीकता/पारदर्शिता

2720. श्री राजेश रंजनः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विशेषकर रोजगार और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में सरकारी आंकड़ों की सटीकता और पारदर्शिता के साथ मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) सांख्यिकीय आंकड़ों की निरंतरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों में आंकड़ा संग्रहण पद्धतियों और परिभाषाओं के मानकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता और जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए सरकारी आंकड़ों की समीक्षा और विधिमान्यकरण के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ बातचीत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

**उत्तर**

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) गैर-प्रतिदर्श त्रुटियों को न्यूनतम करते हुए लक्षित जनसंख्या से सटीक और विश्वसनीय डेटा प्राप्त होना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय उत्पादों में मजबूत और सुपरिभाषित तंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए बदलती आवश्यकताओं, प्रतिक्रिया और कार्यप्रणाली में प्रगति के आधार पर समय-समय पर सुधार से किए जाते हैं। डेटा संग्रह के चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) या इन-बिल्ट वैधीकरण तंत्र के साथ वेब-आधारित एप्लिकेशन का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्राथमिक डेटा संग्रह किया जा रहा है। बहु-स्तरीय डेटा जांच और वैधीकरण जांच द्वारा डेटा की सटीकता सुनिश्चित की जाती है। संकलात्मक प्रश्नों को संबोधित करने और डेटा गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रशिक्षण तंत्र का पालन किया जाता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही पर जोर देता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का ई-सांख्यिकी पोर्टल डेटा के प्रबंधन

और साझा करने के लिए एक व्यापक प्रणाली उपलब्ध करता है, जिससे नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए समय से और मूल्यवान डेटा इनपुट प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में आधिकारिक आंकड़ों के आसान प्रचार-प्रसार की सुविधा मिलती है।

(ख): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश में सांख्यिकी प्रणाली के नियोजित विकास के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बुनियादी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए डेटा गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी हैं। एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सांख्यिकी के क्षेत्र में मानदंडों और मानकों को निर्धारित करता है और बनाए रखता है, जिसमें अवधारणाएं और परिभाषाएं, डेटा संग्रह कार्यप्रणाली, डेटा प्रसंस्करण और परिणामों का प्रसार शामिल है। इसी क्रम में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डेटा प्रसार: राष्ट्रीय मेटाडेटा संरचना (एनएमडीएस) नामक से अपना प्रकाशन प्रसारित करता है, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली (एनएसएस) के हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य एनएसएस में सामंजस्यपूर्ण गुणवत्ता रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना है, और इस प्रकार प्रक्रियाओं और आउटपुट की आपस में तुलना को सुविधाजनक बनाना है। यह प्रकाशन एनएसएस के सभी हितधारकों और भारतीय आधिकारिक सांख्यिकी के निर्माता, संकलनकर्ता और प्रसारक के रूप में उनकी भूमिकाओं में अन्य लोगों पर लागू होता है। संबंधित मंत्रालय/विभागों के साथ भी समय-समय पर विचार-विमर्श किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली परिभाषाएँ यथासंभव समान रूप से अपनाई जाएँ।

(ग): आधिकारिक आंकड़ों की समीक्षा और उन्हें मान्य करने के उद्देश्य से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने समितियां/कार्य समूह (डब्ल्यूजी) गठित किए हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शिक्षा, अनुसंधान, अर्थशास्त्र, वित्त आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ये समितियां/कार्य समूह सरकार के भीतर और/या बाहर इस विषय के विषय विशेषज्ञों की सहायता भी ले सकते हैं और विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें सदस्य के रूप में भर्ती कर सकते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए जा रहे आंकड़ों के बारे में उनकी प्रतिक्रिया को शामिल करने और समझ को बढ़ाने के लिए डेटा उपयोगकर्ताओं/हितधारकों के साथ नियमित संवाद भी आयोजित किए जाते हैं।

******